सुरक्षित स्कूलों का घोषणा-पत्र

शिक्षा पर सशस्त्र संघर्ष का असर जरूरी मानवीय, विकास सम्बन्धी और व्यापक सामाजिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है. दुनिया भर में स्कूलों और विश्वविद्यालयों पर बमबारी और गोलीबारी हुई और उन्हें जलाया गया और बच्चों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षाविदों की हत्या की गई, वे घायल हुए, उनका अपहरण हुआ या वे मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए हैं. सशस्त्र संघर्षों के पक्षों द्वारा शैक्षणिक सुविधाओं का उपयोग, अन्य मकसदों के साथ-साथ, छावनियों, बैरकों या हिरासत केंद्रों के रूप में किया जाता रहा है. इस तरह के कार्य विद्यार्थियों और शिक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाते हैं, बड़ी संख्या में बच्चों और विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हैं और इस तरह समुदायों से वह बुनियाद छीन लेते हैं जिस पर वह अपना भविष्य गढ़ता है. कई देशों में, सशस्त्र संघर्ष न सिर्फ स्कूल के बुनियादी ढांचे बल्कि बच्चों की एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर रहा है.

शैक्षणिक सुविधाओं, छात्रों और शिक्षा कर्मियों के खिलाफ हिंसा शिक्षा पर होने वाले हमलों में शामिल हैं. हमला और हमले की धमकी, व्यक्ति और समाजों को गंभीर और दीर्घकालीन नुकसान पहुंचा सकते हैं. शिक्षा तक पहुंच सीमित हो सकती है; शैक्षणिक सुविधाओं का कामकाज अवरुद्ध किया जा सकता है या अपनी सुरक्षा की चिंता से शिक्षाकर्मी और विद्यार्थी शिक्षा से दूर हो सकते हैं. स्कूलों और विश्वविद्यालयों पर हमलों का इस्तेमाल असहिष्णुता और बहिष्करण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. जैसे कि, लड़कियों की शिक्षा रोक कर लैंगिक भेदभाव बढ़ाने, कुछ समुदायों के बीच संघर्ष कायम रखने, सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबंधित करने और अकादमिक स्वतंत्रता या संघ बनाने के अधिकार से वंचित करने के लिए. जहां शैक्षणिक सुविधाओं का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, वहां सशस्त्र पक्षों द्वारा बच्चों को भर्ती और उनका इस्तेमाल करने का जोखिम बढ़ सकता है या बच्चों और युवाओं के यौन शोषण या उत्पीड़न के चपेट में आने का खतरा रहता है. विशेष रूप से, यह शिक्षा संस्थानों पर हमले की संभावना को बढ़ा सकता है.

इसके विपरीत, मृत्यु, चोट और शोषण से बच्चों और युवाओं की रक्षा करने में शिक्षा मदद कर सकती है; यह सामान्य जीवन और स्थिरता की पेशकश कर सशस्त्र संघर्ष के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम कर सकती है और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं से जोड़ सकती है. 'संघर्ष के प्रति संवेदनशील' शिक्षा संघर्ष में सहायक होने से बचती है और शांति के लिए पहल करती है. शिक्षा विकास और मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता के पूर्ण उपभोग का आधार है. हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि शिक्षा के संस्थान सुरक्षा के स्थान बने रहें.
हम शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा और सुरक्षा देने एवं सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में पठन-पाठन जारी रखने के लिए अलग-अलग देशों की पहल का स्वागत करते हैं. पढाई जारी रखने से न केवल जीवन-रक्षक स्वास्थ्य जानकारी प्रदान की जा सकती है बल्कि सशस्त्र संघर्षों का सामना करने वाले समाज में विशिष्ट जोखिमों के बारे में सलाह भी दी जा सकती है.

हम बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काम की प्रशंसा करते हैं और सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ होने वाले गंभीर उल्लंघन के निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हैं. हम सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1998 (2011) और 2143 (2014) के महत्व पर जोर देते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ सशस्त्र संघर्षों के पक्षों से उन कार्यों से बचने की दरख्वास्त करते हैं जो बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में बाधा पहुंचाते हैं एवं लागू अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सशस्त्र बलों और सशस्त्र गैर-राज्य समूहों द्वारा स्कूलों के उपयोग पर रोक के लिए ठोस उपायों पर विचार करने के लिए सदस्य देशों को प्रोत्साहित करते हैं.

हम सशस्त्र संघर्ष के दौरान सैन्य उपयोग से स्कूलों और विश्वविद्यालयों के सुरक्षा के दिशानिर्देशों का स्वागत करते हैं. दिशानिर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, ये स्वैच्छिक दिशानिर्देश हैं जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रभावित नहीं करते हैं. वे मौजूदा अच्छे कार्यों को बढ़ावा देते हैं और इनका मकसद ऐसा मार्गदर्शन देना है जिससे कि शिक्षा पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को और कम किया जा सके. हम इन दिशानिर्देशों के प्रचार-प्रसार के प्रयासों का स्वागत करते हैं और सशस्त्र बलों, सशस्त्र समूहों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच उनके वितरण को बढ़ावा देते हैं.

शिक्षा के अधिकार और सभी राष्ट्रों के बीच तालमेल, सहिष्णुता और दोस्ती को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका को स्वीकार कर; सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं, की रक्षा की कार्य प्रणाली के लिए क्रमशः दृढ़ संकल्पित होकर; सभी के लिए सुरक्षित स्कूलों के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध होकर; हम सशस्त्र संघर्ष के दौरान सैन्य उपयोग से स्कूलों और विश्वविद्यालयों के सुरक्षा के दिशा-निर्देशों का समर्थन करते हैं, और हम ये बातें करेंगे:

- दिशानिर्देशों का प्रयोग करेंगे, और उन्हें यथासंभव और उचित रूप में घरेलू नीति और सामरिक संरचना में शामिल करेंगे;
- शैक्षणिक सुविधाओं पर हमलों, हमलों के पीड़ितों और स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों के सैन्य उपयोग पर विश्वसनीय प्रासंगिक आंकड़ा एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे; ऐसे आंकड़ा संग्रहण में मदद करने और पीड़ितों को गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र का भी इस्तेमाल करेंगे;
- लागू राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेंगे और जहां उपयुक्त हो, अपराधियों पर कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे;
- अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और विकास कार्यक्रमों में शिक्षा के 'संघर्ष-संवेदनशील' दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उसे अपनाएंगे और बढ़ावा देंगे और जहां प्रासंगिक हों ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे;
- सशस्त्र संघर्ष के दौरान शिक्षा जारी रखने, शैक्षणिक सुविधाओं के पुनर्स्थापन का समर्थन करने और जहां ऐसा करने की स्थिति में हों, शिक्षा पर हमलों को रोकने या उनका जवाब देने के कार्यक्रमों, इस घोषणा के कार्यान्वयन सहित, को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे;

• बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रासंगिक संगठनों, संस्थाओं और एजेंसियों की कोशिशों का समर्थन करेंगे; और
• प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज को आमंत्रित कर नियमित रूप से बैठक करेंगे, इस प्रकार इस घोषणापत्र के कार्यान्वयन और दिशानिर्देशों के उपयोग की समीक्षा करेंगे.